नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 11
दि. 11.10.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

सीमा पार से घुसपैठ की नई साजिश पाकिस्तान के लॉन्च पैड पर 100 आतंकी तैयार

श्रीनगर। सर्दियों के आगमन से पहले एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से आतंक फैलाने की साजिशें तेज हो गई हैं। खुफिया एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इस समय जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग इलाकों में करीब 60 आतंकी सक्रिय हैं — जिनमें 40 विदेशी (मुख्यतः पाकिस्तानी) और 20 स्थानीय आतंकी शामिल हैं। वहीं, सीमा पार पाकिस्तानी लॉन्च पैड पर 100 से 120 आतंकियों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है, जो बर्फबारी के मौसम में घुसपैठ का प्रयास करने की तैयारी में हैं।

सूत्रों के मुताबिक, इन आतंकियों को इस बार "स्नो इन्फिल्ट्रेशन" की विशेष रणनीति के तहत प्रशिक्षित किया गया है, ताकि वे बर्फ से ढके पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में दाखिल हो सकें। आने वाले दो से तीन महीने सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण बताए जा रहे हैं।

नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह सचिव और सेना व बीएसएफ के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। शाह ने कहा कि आतंकवाद-मुक्त जम्मू-कश्मीर केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और सर्दियों में किसी भी प्रकार की घुसपैठ की कोशिश को विफल करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार रहें। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की जमीन से संचालित हो रहे हैं, और भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा।

सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि सीमा पार के आतंकियों में कई ऐसे हैं जिन्हें "अफगान फ्रंट" पर प्रशिक्षित किया गया था। इनका नेटवर्क बहुत गहराई तक फैला हुआ है और इन्हें स्थानीय स्तर पर भी सहायता मिलती है, जिससे इनकी गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जम्मू-कश्मीर में सक्रिय कई आतंकियों के पास अब अत्याधुनिक हथियार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरण हैं, जो पाकिस्तान से रिमोट ऑपरेशन के जरिए संचालित होते हैं।

बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर के महानिरीक्षक अशोक यादव के अनुसार, नियंत्रण रेखा (LoC) पर सेना और बीएसएफ की संयुक्त चौकसी के कारण पिछले कुछ महीनों में घुसपैठ की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। आधुनिक ड्रोन निगरानी, थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन कैमरों की मदद से सीमा पर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। लेकिन, सर्दियों में बर्फबारी के चलते दृश्यता कम होने से घुसपैठ की कोशिशें बढ़ सकती हैं।

पिछले वर्षों की बड़ी मुठभेड़ों ने देश को कई वीर शहीद दिए हैं। राजौरी के बाजीमाल एनकाउंटर में कैप्टन एमवी प्रांजल, कैप्टन शुभम और हवलदार माजिद ने शहादत दी थी। वहीं, 2023 के कोकेरनाग एनकाउंटर में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट ने आतंकियों से लोहा लेते हुए अपने प्राण न्योछावर किए। इन अभियानों में पाकिस्तान के कई हाई-रैंक आतंकी कमांडर मारे गए थे।

सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, अब घाटी में आतंकियों की नई भर्ती लगभग ठप हो गई है। पहले जहां सोशल मीडिया पर हथियारबंद स्थानीय युवकों की तस्वीरें वायरल होती थीं, अब ऐसे मामले बेहद कम हैं। मौजूदा आतंकी या तो पुराने संगठन के बचे हुए सदस्य हैं या फिर स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। ये "हाइब्रिड टेरर" रणनीति के तहत छोटे पैमाने के हमलों की योजना बनाते हैं ताकि सुरक्षा बलों का ध्यान बंटाया जा सके।

अमित शाह ने बैठक के अंत में कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के ढांचे को जड़ से खत्म किया जा चुका है, लेकिन अब समय है कि सीमा पार से होने वाली हर कोशिश को निर्णायक रूप से समाप्त किया जाए। उन्होंने सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दी और साफ कहा — "किसी भी कीमत पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। जम्मू-कश्मीर में अब सिर्फ शांति और विकास की कहानी लिखी जाएगी।"

मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैट्स की जबरदस्त डिमांड डालीबाग के 72 फ्लैटों के लिए 4200 से ज्यादा लोगों ने दिखाई रुचि

लखनऊ। कभी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के कब्जे में रही लखनऊ की डालीबाग की जमीन अब गरीबों के सपनों का घर बन गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना के तहत इस जमीन पर बनाए गए 72 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) फ्लैटों की जबरदस्त मांग देखी जा रही है। महज एक सप्ताह में ही 4200 से अधिक लोगों ने इन फ्लैटों को खरीदने में रुचि दिखाई है। एलडीए अधिकारियों के मुताबिक, इन फ्लैटों की कीमत मात्र 10.70 लाख रुपये से शुरू होती है, जो लखनऊ के इस पॉश इलाके के लिहाज से बेहद सस्ती मानी जा रही है। आवेदन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू हुई है और 3 नवंबर तक चलेगी। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अब तक करीब 300 लोगों ने औपचारिक रूप से रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। यह जमीन कभी मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी, जिसने 2007 में फर्जी कागजातों के जरिए यहां एक आलीशान बंगला बनवाया था। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद "माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस" नीति के तहत इस अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया गया। 2020 में एलडीए ने कार्रवाई कर बंगला ध्वस्त कराया और 20,000 वर्गफुट की इस प्रीमियम जमीन को सरकारी खाते में दर्ज किया। सूत्रों के अनुसार, मुख्तार अंसारी के गिरोह से जुड़ी करीब 600 करोड़ रुपये की संपत्तियों को या तो ध्वस्त किया गया या सरकारी योजनाओं में शामिल कर लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह तय किया गया कि जब्त की गई संपत्तियों को जनकल्याण के कामों में लगाया जाएगा। इसके तहत दिसंबर 2023 में एलडीए ने इस भूमि पर ईडब्ल्यूएस आवासीय परियोजना का निर्माण शुरू किया था, जो अब पूरी तरह तैयार है।

एलडीए के अनुसार, डालीबाग की यह परियोजना राजधानी के केंद्र में होने के कारण आवासीय दृष्टि से बेहद आकर्षक है। प्राइम लोकेशन, आधुनिक निर्माण और सस्ती कीमतों के कारण इन फ्लैटों की मांग तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा, एलडीए ने देवपुर पारा क्षेत्र में भी 2,568 फ्लैट बनाए हैं, जिनकी कीमत 9.82 लाख रुपये से शुरू होती है। मुख्तार अंसारी की मृत्यु 28 मार्च 2024 को बांदा जेल में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद भी सरकार ने यह संदेश स्पष्ट किया कि अपराध की जमीन पर अब सिर्फ जनहित के सपने पनपेंगे। डालीबाग की यह परियोजना उसी संकल्प का प्रतीक मानी जा रही है — जहां कभी माफिया राज था, अब गरीबों का घर और विकास की कहानी लिखी जा रही है।

सरकारी बैंकों में अब निजी क्षेत्र के अफसरों को भी मौका,एमडी और ईडी पदों के लिए खुला रास्ता, एसबीआई में शुरू होगी नई व्यवस्था

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सुधार करते हुए शुक्रवार को यह घोषणा की कि अब देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) भी शामिल है, शीर्ष प्रबंधन पदों पर निजी क्षेत्र के अफसरों की नियुक्ति संभव होगी। इससे सरकारी बैंकों के संचालन और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है।

नए दिशा-निर्देशों के तहत एसबीआई में प्रबंध निदेशक (एमडी) के चार पदों में से एक पद अब निजी क्षेत्र या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के अनुभवी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगा। अब तक एसबीआई और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में एमडी और चेयरमैन के सभी पद केवल आंतरिक अधिकारियों से ही भरे जाते थे।

सरकार की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार, न केवल एसबीआई बल्कि देश के अन्य 11 प्रमुख सरकारी बैंक—जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया आदि—में भी निजी क्षेत्र के उम्मीदवार कार्यकारी निदेशक (ईडी) या एमडी पद के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इन पदों के लिए पात्रता मानदंड भी तय किए गए हैं। एमडी पद के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 21 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, जिसमें 15 वर्ष का बैंकिंग अनुभव और बोर्ड स्तर पर न्यूनतम दो वर्षों का कार्यकाल शामिल होगा। वहीं, ईडी पद के लिए कम से कम 18 वर्षों का अनुभव आवश्यक होगा, जिसमें 12 वर्ष बैंकिंग क्षेत्र का और तीन वर्ष उच्च प्रबंधकीय स्तर पर कार्य का होना चाहिए।

नए दिशा-निर्देशों के लागू होते ही एसबीआई के एमडी का एक पद स्वतः रिक्त माना जाएगा ताकि नई प्रक्रिया के तहत नियुक्ति की जा सके। इसके बाद, बनने वाली अन्य रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों से भरी जाएंगी।

इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) जैसे संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारी एमडी या ईडी पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

वित्त विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला सरकारी बैंकों में निजी क्षेत्र की दक्षता और प्रोफेशनल कल्चर को लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं, यूनियन प्रतिनिधियों और बैंकिंग कर्मियों के संगठनों का मानना है कि इससे भविष्य में सरकारी बैंकों की स्वायत्तता और नीति निर्धारण पर भी गहरा असर पड़ सकता है।

फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि निजी क्षेत्र से आने वाले पेशेवर किस तरह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नई ऊर्जा और बदलाव लाते हैं, या फिर यह कदम परंपरागत बैंकिंग ढांचे में विवाद का विषय बनता है।

सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले में केरल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश SIT को जांच सौंपते हुए छह हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

कोच्चि। सबरीमाला मंदिर में सोने की हेराफेरी के मामले ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मंदिर के द्वारपालक प्रतिमाओं से सोने की चोरी के आरोपों पर संज्ञान लेते हुए पुलिस को मामला दर्ज करने और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित कर जांच शुरू करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अब तक की प्राथमिक जांच से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि मंदिर में मौजूद दो प्रतिमाओं से सोने की हेराफेरी हुई है।

जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस के वी जयकुमार की खंडपीठ ने कहा कि SIT छह सप्ताह के भीतर जांच पूरी करे और हर दो हफ्ते में जांच की स्थिति रिपोर्ट अदालत में पेश करे। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जांच से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी मीडिया या अन्य माध्यमों में लीक नहीं होनी चाहिए, ताकि जांच की निष्पक्षता बनी रहे।

अदालत के अनुसार, प्रारंभिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि सोने की परत चढ़ाने का काम संभालने वाले व्यक्ति उन्नीकृष्णन पोट्टी को बड़ी मात्रा में सोना सौंपा गया था। जांच में यह भी पाया गया कि पोट्टी को लगभग 474.9 ग्राम सोना दिया गया था, जिसका उपयोग प्रतिमाओं पर चढ़ाने के लिए होना था। लेकिन जांच के दौरान यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पूरा सोना प्रतिमाओं पर लगाया गया या उसका कुछ हिस्सा गायब हो गया।

हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को "श्रद्धा से जुड़ा गंभीर आर्थिक अपराध" बताते हुए कहा कि सबरीमाला जैसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल की गरिमा को बनाए रखने के लिए जांच में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मंदिर प्रशासन और त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि SIT को जांच में पूरा सहयोग दिया जाएगा। वहीं, राज्य सरकार ने भी मामले को गंभीर बताते हुए कहा है कि यदि जांच में किसी भी अधिकारी या ठेकेदार की संलिप्तता पाई जाती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबरीमाला मंदिर में सोने की परत चढ़ाने का यह प्रोजेक्ट कई साल पहले 'नवोन्नेषण योजना' के तहत शुरू किया गया था। मंदिर के गेट पर रखी दोनों द्वारपालक प्रतिमाओं पर सोने की परत चढ़ाने का काम मंदिर के दानदाताओं और प्रायोजकों की मदद से कराया गया था। अब कोर्ट की निगरानी में चल रही यह जांच तय करेगी कि धार्मिक आस्था के प्रतीक इस स्वर्ण प्रोजेक्ट में आखिर सोना कहां और कैसे गायब हो गया।

अमेरिका ने ईरान को ऊर्जा व्यापार में मदद करने वालों पर कसा शिकंजा,दो भारतीय नागरिकों समेत 50 कंपनियों और पोतों पर प्रतिबंध

वाशिंगटन। अमेरिका ने ईरान के पेट्रोलियम व्यापार में शामिल नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने शुक्रवार को दो भारतीय नागरिकों समेत दुनिया भर की 50 कंपनियों और जहाजों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां और व्यक्ति ईरान के तेल और एलपीजी उत्पादों के अवैध निर्यात में मदद कर रहे थे, जिससे तेहरान को अरबों डॉलर की आमदनी हुई। यह धनराशि, अमेरिका के अनुसार, आतंकवादी संगठनों और उसके विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। OFAC की रिपोर्ट के मुताबिक, इन कंपनियों ने जटिल व्यापारिक नेटवर्क, शिपिंग रूट और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए ईरान के पेट्रोलियम उत्पादों को एशियाई देशों तक पहुंचाया। अमेरिकी प्रशासन ने इसे "वैश्विक ऊर्जा स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा" बताया है। प्रतिबंधित भारतीय नागरिकों में वरुण पूला का नाम प्रमुख है, जो मार्शल द्वीप स्थित बर्था शिपिंग इंक के मालिक हैं। उनकी कंपनी का जहाज 'पामिर' कोमोरोस झंडे के तहत चलाया जा रहा था और जुलाई 2024 से चीन तक लगभग 40 लाख बैरल ईरानी एलपीजी की आपूर्ति कर चुका था। वहीं, दूसरी भारतीय नागरिक सोनिया श्रेष्ठा, मुंबई की वेगा स्टार शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की मालिक हैं। उनका पोत 'नेप्टा', जनवरी 2025 से पाकिस्तान को ईरानी एलपीजी की खेप पहुंचा रहा था।

अमेरिकी वित्त विभाग ने कहा कि इन दोनों नागरिकों, उनकी कंपनियों और उनसे जुड़े जहाजों की अमेरिका में स्थित सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी। इसके अलावा जिन कंपनियों में इनकी 50 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी है, वे भी स्वचालित रूप से प्रतिबंधों के दायरे में आ गई हैं। अमेरिका ने यह भी चेतावनी दी है कि ईरान की ऊर्जा बिक्री में शामिल किसी भी संस्था या व्यक्ति के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। इस कदम को वाशिंगटन की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वह ईरान पर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के जरिए उसके परमाणु कार्यक्रम और आतंक समर्थक गतिविधियों को रोकना चाहता है।

भारत में घट रही है धूप की अवधि: 30 साल में मैदानों में 13 घंटे और पहाड़ों पर नौ घंटे की कमी

वाराणसी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) और देशभर के मौसम वैज्ञानिकों के एक व्यापक अध्ययन में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि भारत में धूप की अवधि यानी सोलर रेडिएशन लगातार घट रही है। इसे वैज्ञानिक भाषा में सोलर डिमिंग कहा जाता है। शोध में पाया गया कि पिछले 30 वर्षों में मैदानों में औसतन 13 घंटे और पहाड़ी इलाकों में करीब नौ घंटे तक सूर्य के प्रकाश की अवधि घट गई है। इस गिरावट के पीछे वायु प्रदूषण, औद्योगिकीकरण और तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण को मुख्य कारण बताया गया है।

अध्ययन के अनुसार, 1988 से 2018 के बीच देशभर में सूर्य के प्रकाश की औसत अवधि घटती चली गई। खास तौर पर उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई, जहां हर साल लगभग आधा घंटा तक धूप घटती चली गई। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि यही प्रवृत्ति जारी रही, तो भारत की सौर ऊर्जा क्षमता, कृषि उत्पादन और जलवायु संतुलन पर दीर्घकालिक असर पड़ेगा।

यह अध्ययन नेचर पोर्टफोलियो की प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका 'साइंटिफिक रिपोर्ट्स' में प्रकाशित हुआ है। इस शोध को बीएचयू के मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) दिल्ली और भारत मौसम विभाग (IMD) ने संयुक्त रूप से पूरा किया। देश के नौ अलग-अलग जलवायुवीय क्षेत्रों में स्थित 20 प्रमुख मौसम केंद्रों से 30 वर्षों का डेटा एकत्र कर उसका विश्लेषण किया गया।

अध्ययन में पाया गया कि हिमालयी क्षेत्र में प्रति वर्ष लगभग 9 घंटे धूप की अवधि कम हुई है, जबकि पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में यह गिरावट 8.6 घंटे प्रति वर्ष रही। वहीं, पूर्वी तट और मध्य भारत में गिरावट मध्यम स्तर की रही, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में धूप की अवधि में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया।

बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह कमी मुख्य रूप से मानसून और उसके बाद के महीनों में अधिक दर्ज की गई है। बादलों की अधिकता, धूल और प्रदूषक तत्वों के कारण वायुमंडल में सूर्य के विकिरण की तीव्रता घट रही है। प्रदूषण के कारण वातावरण में सूक्ष्म कण (एयरोसोल्स) सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह तक कम प्रकाश पहुंच पाता है। उन्होंने बताया कि भारत के अधिकांश शहरों में वायु प्रदूषण पिछले दो दशकों में रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा है। यही कारण है कि बड़े शहरों में आसमान अक्सर धुंध से ढका रहता है। इस "डिमिंग इफेक्ट" के कारण सौर पैनलों की कार्यक्षमता में भी कमी आई है, जिससे भारत की सौर ऊर्जा नीति के लक्ष्यों को चुनौती मिल सकती है।

शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सोलर डिमिंग की यह प्रवृत्ति जारी रही तो इसका असर भारत के कृषि क्षेत्र पर भी पड़ेगा, क्योंकि फसलों की प्रकाश-संश्लेषण प्रक्रिया (फोटोसिंथेसिस) प्रभावित होगी। इससे उत्पादन घटने की संभावना है।

इस बीच, बीएचयू की ताजा मौसम रिपोर्ट में बताया गया है कि बनारस गुरुवार को 33.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का पांचवां सबसे गर्म जिला रहा। दिन और रात के तापमान में 10 डिग्री का अंतर दर्ज किया गया। वहीं, अक्टूबर के पहले दस दिनों में यहां 771 फीसदी अधिक वर्षा हो चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पछुआ हवा कुछ दिनों में सक्रिय होगी, जिससे तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है और मौसम में ठंडक बढ़ेगी। वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि यह केवल जलवायु परिवर्तन का नहीं, बल्कि "मानवजनित हस्तक्षेप" का भी परिणाम है। यदि प्रदूषण नियंत्रण के ठोस उपाय नहीं किए गए, तो आने वाले दशकों में भारत के कई हिस्सों में "सूरज की रोशनी का समय" और भी कम हो सकता है — जो न केवल पर्यावरण बल्कि ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरे का संकेत है।

100% फीस वृद्धि मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त,दिल्ली सरकार और निजी स्कूल संगठन से जवाब तलब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा शिक्षा निदेशालय की अनुमति के बिना 100 प्रतिशत तक फीस बढ़ाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार और निजी स्कूलों के संगठन एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह मामला नया समाज अभिभावक संघ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि दिल्ली के कई निजी स्कूलों ने पिछले कुछ वर्षों में मनमाने तरीके से फीस में 100 प्रतिशत तक की वृद्धि की है, जबकि उन्हें सरकार से रियायती दर पर जमीन इस शर्त पर दी गई थी कि वे किसी भी फीस बढ़ोतरी से पहले शिक्षा निदेशालय (डीओई) से अनुमति लेंगे। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने निजी स्कूल संगठन के वकील से तीखा सवाल किया — "आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? क्या आप मानते हैं कि निदेशालय की अनुमति के बिना फीस बढ़ाना उचित है?" अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा के अधिकार और अभिभावकों के हितों की अनदेखी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती। अदालत ने दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा है कि उसने अब तक इस मामले में क्या कदम उठाए हैं और क्या शिक्षा निदेशालय ने संबंधित स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। याचिका में कहा गया है कि कई निजी स्कूलों ने कोविड-19 महामारी के बाद से ही फीस में मनमानी बढ़ोतरी शुरू की, जबकि उस समय सरकार ने राहत के तौर पर फीस न बढ़ाने का आदेश दिया था।

संपादकीय

ब्रिटेन उदार वीज़ा नीति का लाभ भी दे

ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने निरंकुश टैरिफ थोपने व भारत के हितों पर कुठाराघात की नीति अख्तियार की हुई है, ब्रिटेन के साथ रक्षा व कारोबारी रिश्तों में नई शुरुआत उम्मीद जगाने वाली है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते का सिरे चढ़ना दोनों पक्षों के हित में बताया जा रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा को नई दिल्ली और लंदन के संबंधों में एक नये सिरे से बदलाव का प्रतीक बताया जा रहा है। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात के प्रतीकात्मक और व्यावहारिकता की दृष्टि से गहरे निहितार्थ हैं। इस यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण समझौते इस यात्रा के महत्व को रेखांकित करते हैं। जिसमें 468 मिलियन डॉलर का मिसाइल सौदा, मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के शीघ्र क्रियान्वयन के लिये प्रतिबद्धता तथा भारत में नौ ब्रिटिश विश्वविद्यालय खोलने पर सहमत होना शामिल है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि इस रिश्ते में 'एक नई ऊर्जा है', जो व्यापार, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा का समन्वय चाहती है। हालांकि, मुक्त व्यापार समझौते का मूल्यांकन, इसके प्रतीकात्मक मूल्य के बजाय इसके वास्तविक आर्थिक प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए। मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन के बाद भारत के लिये ब्रिटिश बाजार तक भारतीय कपड़ों, दवा और सेवाओं, विशेष रूप से आईटी और फिनटेक के निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन को लेकर कुछ चिंताएं भी मौजूद हैं। मसलन छोटे और मध्यम उद्यमों के सामने सस्ते ब्रिटिश आयातों से कमजोर होने या नियामक विषमताओं का सामना करने की आशंका बनी हुई है। इसमें दो राय नहीं है कि एफटीए के फलस्वरूप, ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन के लिये, भारत एक अनिश्चित वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच विकास का एक लाभप्रद अवसर और एक स्थिर अर्थव्यवस्था वाला मजबूत साझेदार का मिलना है। लेकिन इसके बावजूद मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन में भारतीय हितों की रक्षा के लिये सतर्क पहल की जरूरत भी महसूस की जा रही है।

वैसे यह भी तथ्य है कि अनुसंधान, डिजिटल नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा में पारस्परिक निवेश की कसौटी पर ही दोनों देशों के रिश्तों की असली परीक्षा होगी। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि भारतीय पेशेवरों या छात्रों के लिए वीजा मानदंडों में ढील देने से स्टारमर का स्पष्ट इनकार करना इस बहुप्रचारित साझेदारी की सार्थकता को लेकर सवाल पैदा कर सकता है। यह विडंबना ही है कि ब्रिटेन कुछ मुद्दों को लेकर दोहरा मापदंड अपना रहा है। एक ओर ब्रिटेन जहां भारतीय बाजार में अपनी पहुंच बनाना और साथ ही तकनीकी सहयोग तो पाना चाहता है, लेकिन वहीं वह श्रम की गतिशीलता को लेकर सतर्क बना हुआ है, जो कि ब्रिटेन के साथ भारत के आर्थिक और शैक्षिक जुड़ाव का एक केंद्रीय मुद्दा बना रहा है। इस बात में दो राय नहीं हो सकती है कि यदि प्रतिभाओं का आदान-प्रदान एकतरफा ही रहेगा, तो पारस्परिक लाभ पर साझेदारी फल-फूल नहीं सकती। निर्विवाद रूप से यह तथ्य तार्किक है कि मुक्त व्यापार समझौते की राह अभी भी बाधाओं से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पायी है। उल्लेखनीय है कि टैरिफ, बौद्धिक संपदा और श्रम गतिशीलता के मुद्दे पर मतभेद अभी भी बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मूल्य आधारित कूटनीति पर भारतीय प्राथमिकता को लेकर दोनों देशों में मतभेद सामने आ सकते हैं। साथ ही यह भी जरूरी है कि दोनों पक्षों को पुरानी कसक से प्रेरित कूटनीति से आगे बढ़ने की जरूरत होगी। निर्विवाद रूप से विशेष संबंध औपनिवेशिक हैंगओवर या प्रवासी भावना पर आधारित नहीं हो सकते। इस साझेदारी का वायदा एक ऐसे सतत सहयोग के निर्माण में निहित है, जिसमें दोनों देशों के आम नागरिकों को वास्तविक लाभ मिल सके। भारत की चिंता ब्रिटेन की भूमि से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले तत्वों पर अंकुश लगाने को लेकर भी है। निश्चय ही अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अराजकता नहीं हो सकता। हाल के दिनों में कुछ अप्रिय घटनाएं भारतीय लोकतंत्र के प्रतीकों पर प्रहार करने के रूप में सामने आ चुकी हैं।

भारत पर लगाई शर्तें और अमेरिका को दिया जवाब रेयर अर्थ के जरिये चीन ने चली नई सामरिक चाल

> हम आपको बता दें कि चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने हाल ही में रेयर अर्थ और उनसे जुड़ी तकनीकों के निर्यात पर नए प्रतिबंध घोषित किए हैं। अब कोई भी विदेशी कंपनी यदि चीन से निकले इन तत्वों का उपयोग करती है तो उसे विशेष अनुमति लेनी होगी।

वैश्विक शक्ति-संतुलन अब केवल सैन्य बल या आर्थिक आकार से नहीं, बल्कि उन तत्वों की उपलब्धता से भी तय हो रहा है जिन्हें "रेयर अर्थ मेटल्स" कहा जाता है। यह वह दुर्लभ खनिज हैं जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक, रक्षा और हरित तकनीकों की आत्मा हैं। इन्हीं पर चीन ने एक बार फिर नियंत्रण कसते हुए दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि आने वाले वर्षों में वह केवल विनिर्माण महाशक्ति ही नहीं, बल्कि संसाधन-सर्वोच्चता की भूमिका भी निभाना चाहता है।हम आपको बता दें कि चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने हाल ही में रेयर अर्थ और उनसे जुड़ी तकनीकों के निर्यात पर नए प्रतिबंध घोषित किए हैं। अब कोई भी विदेशी कंपनी यदि चीन से निकले इन तत्वों का उपयोग करती है तो उसे विशेष अनुमति लेनी होगी। नये प्रतिबंधों में न केवल कच्चे खनिज शामिल हैं, बल्कि खनन, स्मेल्टिंग, रीसाइक्लिंग और मैग्नेट निर्माण तकनीक तक को नियंत्रण के दायरे में लाया गया है। यह कदम उस समय उठाया गया है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव नई ऊँचाइयों पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उच्च-टैरिफ नीति के जवाब में चीन ने रेयर अर्थ की आपूर्ति को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया है।

हम आपको बता दें कि विश्व में रेयर अर्थ का लगभग 70% खनन और 90% प्रसंस्करण (processing) चीन के नियंत्रण में है। यानी दुनिया की डिजिटल और सैन्य प्रगति की धुरी बीजिंग के हाथ में है। इसी संदर्भ में चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स की आपूर्ति के लिए जो शर्तें रखी हैं, वह केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि भूराजनैतिक प्रकृति की हैं। बीजिंग ने कहा है कि भारत को ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स तभी मिलेंगे जब वह यह सुनिश्चित करेगा कि इनका उपयोग केवल घरेलू जरूरतों के लिए होगा और ये किसी भी रूप में अमेरिका तक नहीं पहुँचेंगे।

भारतीय कंपनियों ने "एंड-यूज़र सर्टिफिकेट" (EUC) देकर यह आश्वासन दिया है कि इन मैग्नेट्स का उपयोग विनाशकारी हथियारों के निर्माण या सैन्य उत्पादन में नहीं किया जाएगा। लेकिन चीन ने भारत से यह भी आश्वासन माँगा है कि वह अमेरिका को इन तत्वों तक पहुँचने से रोकने की गारंटी दे। यही वह बिंदु है जो चीन की नीति का असली उद्देश्य उजागर करता है। यानि वह भारत को अपने नियंत्रण तंत्र में बाँधना चाहता है ताकि अमेरिका–भारत तकनीकी गठजोड़ को सीमित किया जा सके।

चीन ने अपने इन कदमों को "राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा" के लिए आवश्यक बताया है। परंतु विश्लेषकों का मानना है कि यह "सुरक्षा" की आड़ में रणनीतिक संसाधनों के हथियारकरण की नीति है। यह अमेरिका की "चिप एक्सपोर्ट कंट्रोल" नीति का जवाब है, जिसमें वाशिंगटन ने चीन को उच्च-स्तरीय सेमीकंडक्टर तकनीक देने पर प्रतिबंध लगाया था। अब बीजिंग उसी भाषा में जवाब दे रहा है— "यदि तुम हमें चिप्स नहीं दोगे, तो हम तुम्हें रेयर अर्थ नहीं देंगे।" साथ ही भारत जैसे देशों से वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वह उसकी इस "रणनीतिक घेराबंदी" को कमजोर न करें।

देखा जाये तो भारत की दृष्टि से यह परिस्थिति दोहरी चुनौती प्रस्तुत करती है। एक ओर, भारत की ईवी (Electric Vehicle), नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग इन रेयर अर्थ तत्वों पर निर्भर हैं। दूसरी ओर, चीन द्वारा लगाई गई "अमेरिका-निरोधक शर्तें" भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को चुनौती देती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में ईवी निर्माण में प्रयुक्त मोटरों के 12 से अधिक घटकों में रेयर अर्थ मैग्नेट्स की आवश्यकता होती है। हल्के रेयर अर्थ के निर्यात को चीन ने फिर से शुरू कर दिया है, परंतु भारी रेयर अर्थ मैग्नेट्स की आपूर्ति पर नियंत्रण अब भी जारी है। इसका सीधा असर बड़े वाहनों, बसों और इलेक्ट्रिक ट्रकों के निर्माण पर पड़ रहा है।

इसके अलावा, दो-पहिया निर्माता फिलहाल हल्के मैग्नेट या फेराइट मैग्नेट का उपयोग कर रहे हैं, परंतु इससे दक्षता घट जाती है और उत्पादन लागत बढ़ जाती है। इसलिए भारत के लिए यह स्थिति एक सख्त संदेश है कि "सप्लाई चेन की स्वतंत्रता" अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन चुकी है।

देखा जाये तो चीन की यह नीति केवल भारत या अमेरिका के खिलाफ नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के पुनर्गठन का हिस्सा है। वह यह जताना चाहता है कि यदि पश्चिमी देश तकनीकी निर्यात पर रोक लगाएंगे, तो चीन अपने खनिज संसाधनों के वर्चस्व से जवाब देगा। चीन का यह कदम यह भी दिखाता है कि भविष्य की विश्व राजनीति 'खनिज प्रभुत्व' पर आधारित होगी। अमेरिका पहले ही इस दिशा में कदम उठा चुका है। उसने अपने घरेलू रेयर अर्थ उद्योग में $520 मिलियन का निवेश किया है और MP Materials जैसी कंपनियाँ अमेरिका के भीतर "Mine-to-Magnet" आपूर्ति श्रृंखला बनाने में जुटी हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा होने में वर्षों लगेंगे। तब तक दुनिया को चीन की शर्तें माननी ही होंगी।

देखा जाये तो भारत को इस परिदृश्य में दो रास्तों में से एक चुनना होगा। या तो चीन पर निर्भर रहकर उसके बनाए गए नियंत्रण ढाँचे को स्वीकार करे, या अपने घरेलू रेयर अर्थ खनन और प्रसंस्करण उद्योग को सशक्त बनाकर स्वतंत्र आपूर्ति श्रृंखला तैयार करे। मोदी सरकार के पास अब यह अवसर है कि वह "क्रिटिकल मिनरल मिशन" को उसी प्राथमिकता से आगे बढ़ाए, जिस तरह "चिप मिशन" को बढ़ाया गया है। भारत के पास अंडमान, ओडिशा और अरुणाचल जैसे क्षेत्रों में रेयर अर्थ के पर्याप्त भंडार हैं, आवश्यकता केवल तकनीकी निवेश और नीति-साहस की है। कुल मिलाकर देखें तो चीन की शर्तों का वास्तविक अर्थ यही है कि जो देश संसाधन-निर्भर रहेगा, वह रणनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं रह सकेगा।

प्रेरणा

धर्मराज युधिष्ठिर और यक्ष संवाद से उपजा मानवता का सत्य

महाभारत के वनपर्व में वर्णित यक्ष-युधिष्ठिर संवाद भारतीय चिंतन की उन अमर घटनाओं में से एक है, जहाँ केवल कुछ प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से संपूर्ण जीवन-दर्शन को व्यक्त कर दिया गया। यह प्रसंग न केवल धर्म की व्याख्या करता है, बल्कि यह भी बताता है कि 'मानव धर्म' वास्तव में क्या है और उसका आधार कहाँ है।

पांडव वनवास में थे। दिन-रात संघर्षों और कष्टों के बीच भी युधिष्ठिर अपने धर्म और संयम से कभी विचलित नहीं हुए। एक दिन वे अपने भाइयों के साथ अत्यंत प्यासे होकर एक वन से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई सहदेव को जल लाने भेजा। सहदेव जब सरोवर के पास पहुँचे, तो एक अदृश्य यक्ष की आवाज़ आई—"रुको! यह जल देवताओं का है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी इसे पी सकते हो।" लेकिन सहदेव ने बिना उत्तर दिए ही जल पीने की चेष्टा की और तुरंत निर्जीव होकर गिर पड़े। फिर एक-एक करके नकुल, अर्जुन और भीम भी वही भाग्य को प्राप्त हुए। अंततः युधिष्ठिर स्वयं वहाँ पहुँचे।

उन्होंने उसी यक्ष के स्वर को सुना, लेकिन अधीरता नहीं दिखाई। उन्होंने विनम्रता से कहा—"हे देव! आप कौन हैं? आपके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना मैं जल नहीं पीऊँगा।" यक्ष प्रसन्न हुआ और बोला—"हे धर्मराज, यदि तुम मेरे प्रश्नों का सत्य उत्तर दोगे, तो तुम्हारे भाइयों को जीवनदान दूँगा।" फिर आरंभ हुआ वह गूढ़ और अतुलनीय संवाद—

पहला प्रश्न था—"कौन व्यक्ति शोक नहीं करता?"

युधिष्ठिर बोले—"जिसने अपने मन को वश में कर लिया, वही शोक नहीं करता। जो अपने विचारों का स्वामी है, वह सुख-दुख, लाभ-हानि, जीवन-मृत्यु सबमें समान रहता है।"

यह उत्तर केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि मानव जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। मनुष्य का सारा दुख उसी के मन की अस्थिरता से उपजता है। जब मन स्थिर होता है, तब बाहरी परिस्थितियाँ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकतीं। यही आत्मसंयम 'मानव धर्म' की पहली शर्त है।

यक्ष ने दूसरा प्रश्न किया—"किसकी मित्रता कभी क्षीण नहीं होती?"

युधिष्ठिर ने कहा—"सज्जनों और संस्कारी लोगों की मित्रता कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि वे अपने संबंधों को स्वार्थ से नहीं, संस्कार से निभाते हैं।"

इस उत्तर में युधिष्ठिर ने जीवन का दूसरा धर्म बताया—'सच्चाई और निष्ठा'। आज के युग में जहाँ संबंध अक्सर लाभ और अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं, वहाँ यह उत्तर मानो सदियों को झकझोर देता है। सच्चा मित्र वह है जो हमारे दुःख में साथ दे, न कि सुविधा के समय।

फिर यक्ष ने पूछा—"धरती से भारी और आकाश से ऊँचा क्या है?"

युधिष्ठिर ने गहरी आस्था के साथ कहा—"धरती से भारी है माँ की ममता, और आकाश से ऊँचा है पिता का अरमान।"

यह उत्तर सुनकर स्वयं यक्ष भी भाव-विह्वल हो उठा। माँ वह शक्ति है जो बिना किसी अपेक्षा के सब कुछ सहती है, और पिता वह जो अपनी संतान को अपने से आगे बढ़ते देख प्रसन्न होता है। यही माता-पिता का प्रेम संसार की सबसे पवित्र भावना है, जो मानव धर्म की जड़ में बसी है।

इन उत्तरों से यक्ष ने समझ लिया कि युधिष्ठिर केवल ज्ञानी नहीं, धर्म के मूर्त रूप हैं। उसने पूछा—"हे धर्मराज, तुमने जीवन के सभी पक्षों को इतने सरल शब्दों में समझा दिया। बताओ, तुम्हारे अनुसार सच्चा धर्म क्या है?"

युधिष्ठिर ने कहा—"धर्म किसी ग्रंथ का पृष्ठ नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय की आवाज़ है। जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, अपने मन को नियंत्रित रखता है, और दूसरों के दुख को अपना मानता है, तब वही धर्मात्मा कहलाता है। धर्म पूजा में नहीं, आचरण में बसता है।"

यक्ष प्रसन्न हो गया। उसने कहा—"हे युधिष्ठिर, तुमने मानव धर्म की सच्ची व्याख्या कर दी है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा ले, अपने वचन का पालन करे और सब जीवों में करुणा रखे, वही सच्चा मानव है।" यह कहकर उसने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवनदान दिया।

उस दिन का वह संवाद युगों-युगों तक गूंजता रहा। उसमें कोई दार्शनिक ग्रंथ नहीं, कोई चमत्कार नहीं—बस एक सरल संदेश था कि मानवता का धर्म किसी जाति, पूजा, या मंत्र में नहीं, बल्कि सत्य, संयम और करुणा में है। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, वही स्वर्ग को पा लेता है, और जिसने दूसरों के हृदय को समझ लिया, वही ईश्वर को पा लेता है।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के तय हों मानदंड

राज्यों के उच्च न्यायालयों व देश के उच्चतम न्यायालय में नदियों में अवैध खनन के मामले दशकों से ले जाये जाते रहे हैं जहां इस बारे राज्य सरकारों को कई बार तीखा भी सुनना पड़ता है। इसके बावजूद स्थिति में बदलाव नहीं। खनन माफिया की शासन पर पकड़ बनी रहती है। नागरिकों की पीड़ा व विरोध उपेक्षित रहते हैं। जिसका प्रमुख कारण सरकारों द्वारा नदी खनन को केवल राजस्व का प्रमुख स्रोत मान लेना है। जबकि, यह पर्यावरण क्षेत्र का विषय भी है।

इसी साल 27 मार्च को लोकसभा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य में जारी व्यापक अवैध नदी खनन और उससे लोगों व पारिस्थितिकी पर कुप्रभाव का मुद्दा उठाया था। जिस पर केन्द्रीय मंत्री का जवाब भी मिला था। उधर इसी संदर्भ में राज्य सरकार का जवाब यह कहकर दिया जा रहा है कि अवैध खनन होता तो खनन से राज्य का राजस्व इतना कैसे बढ़ता। यह दलील तार्किक नहीं लगती। मसलन शराब बिक्री से राजस्व बढ़ रहा है तो क्या राज्य में अवैध शराब की तस्करी नहीं हो रही। असल में राज्य के कई क्षेत्रों में अवैध खनन होता है। पूरे भारत की ही तरह उत्तराखंड में भी नदियों से बेतहाशा अवैध खनन हो रहा है। जहां तक नदी खनन के पारिस्थितिकीय कुप्रभावों की बात है तो वह अवैध खनन से ही नहीं बल्कि वैध खनन से भी हो सकता है। ऐसे में उन मानदंडों को लेकर सार्वजनिक बहस होनी जरूरी है, जो नदियों में खनन की अनुमति देने के पहले के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करने के लिए सभी राज्यों में जरूरी होने चाहिए। यह भेद भी समझें कि खनन के पहले के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के मानक उनसे भिन्न होंगे, जो खनन उपरांत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के लिए हों। आमतौर पर नदियों में जितने खनन की अनुमति ली जाती है , उससे कई गुणा ज्यादा का खनन होता है। ऐसे में बाद के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से ही पता चल पायेगा कि जितने खनिज , जिस जगह से, जितनी लम्बाई चौड़ाई व गहराई से व जिन तरीकों -मशीनों से निकाले जाने की शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी , उनका पालन हुआ या नहीं। ऐसा न होने से पर्यावरण क्षति की पूर्ति कैसे होगी यह भी विचारणीय है। वैज्ञानिक जब नदियों के खनन के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करते हैं , तो वे यह भी देखते हैं , कि नदियों में बहकर जो मिट्टी , बजरी , पत्थर आ रहा है उसकी रासायनिक खनिज संरचना क्या है। नदी में रहते हुये उस खनिज से वनस्पति, जल व जल जीवों पर क्या असर पड़ता है। इनकी निकासी से क्या असर पड़ेगा। इस प्रभाव आकलन में भूजल स्तर पर होने वाला अन्तर , किनारों का कटाव , नये भूस्खलन , भूधंसाव , भूक्षरण के संभावित क्षेत्रों का भी उल्लेख हो। राज्यों में पार्कों व सेंक्चुरियों के पास की नदियों के खनन में मशीनों की आवाज और रोशनी के व तय दूरी बनाये रखने के दिशा निर्देशों की कसौटी पर भी नदी खनन पारिस्थितिकीय प्रभाव आकलन को कसा जायेगा।

वैज्ञानिक खनिज ढुलाई के रास्तों में होने वाले और भण्डारण वाले स्थानों में होने वाले पर्यवरणीय प्रभाव आकलन को भी करते हैं। इसी कारण वे ढुलाई व भण्डारण की शर्तें भी सुझाते हैं।

नदियों में खनन से उनके पार्श्व तल के भूजल स्तर व प्रारूप पर भी असर पड़ता है। किनारे के उन सतही जलाशय क्षेत्रों पर भी असर पड़ जाता है , जहां मछलियां या अन्य जलचर अण्डे - बच्चे देने आते हैं। या वन्यजीव पानी या भोजन की तलाश में आते हैं। प्रवासी पक्षियों के प्रवास पर भी असर पड़ता है। वानस्पतिक जैव विविधता पर भी असर पड़ सकता है। नदियों के खुदान का उनके जल की रासायनिक गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। निस्संदेह पर्यावरणीय पहलुओं के अलावा नदियों के खनन के आर्थिक, सामाजिक व संरचनात्मक विकास के पक्ष को भी नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। रोजगार , निर्माण सामग्री की उपलब्धता व आपदा कार्यों के पुनर्निमाण में दिक्कत व अंतःराज्य निर्माण सामग्री की तस्करी जैसी समस्याएं भी नदी खनन पर रोक से पैदा हो सकती हैं। निर्देश रहते है कि पुलों के पास आवासीय बस्तियों के पास रेत खनन न हो , किन्तु खनन वहां भी होता है। जबकि बिना मिलीभगत अवैध खनन संभव नहीं।

नदियों में रेत खनन के मामले को समग्रता में समझने के लिए एनजीटी का एक निर्देश काफी मददगार है। अप्रैल 2019 में आंध्र प्रदेश सरकार पर अवैध रेत खनन रोकने में असमर्थ रहने पर कुछ निर्देशों के साथ 100 करोड़ रुपये अन्तरिम दण्ड लगाया गया था। मुख्य सचिव को अनियमित रेत खनन पर तुरंत रोक लगाने के आदेशों के साथ साथ चेताया गया था कि प्राकृतिक संसाधनों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है। बेंच का मानना था कि भले ही राज्य सरकार लोगों को निशुल्क रेत देने की कल्याणकारी नीति की बात कर रही हो किन्तु इससे पर्यावरणीय प्रभावों की अनदेखी कर अनियमित रेत खनन का न्यायिक औचित्य सिद्ध नहीं होता है।

अभियान

व्रत के दिन सुई-धागा मत चलाओ – इसके पीछे छिपा है गूढ़ रहस्य और आध्यात्मिक विज्ञान

भारतीय संस्कृति में हर परंपरा के पीछे कोई न कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। आज करवाचौथ के शुभ अवसर पर जब देशभर की महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, तो उनके आचरण से जुड़े कई नियम और निषेध सामने आते हैं। उन्हीं में से एक नियम है कि व्रत के दिन सुई-धागा नहीं चलाना चाहिए। यह बात हर दादी-नानी, मां और बड़ी-बुजुर्ग औरतें अपनी अगली पीढ़ी को समझाती आई हैं। लेकिन क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई दार्शनिक और ऊर्जात्मक कारण भी है?

करवाचौथ का व्रत केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं है, यह एक साधना है जिसमें स्त्री अपने मन, शरीर और आत्मा को संयमित रखती है। वह पूरे दिन बिना अन्न और जल के उपवास रखती है, न केवल अपने पति के दीर्घायु के लिए, बल्कि अपने भीतर की शक्ति, श्रद्धा और भक्ति को स्थिर करने के लिए भी। इस दिन का हर नियम ऊर्जा के संतुलन और ध्यान की गहराई से जुड़ा होता है।

सुई-धागे का काम देखने में सामान्य लगता है, पर यह बहुत सूक्ष्म और केंद्रित मानसिक ऊर्जा मांगने वाला कार्य है। जब कोई व्यक्ति सुई में धागा पिरोता है या कपड़ा सीता है, तो उसका ध्यान भौतिक स्तर पर केंद्रित हो जाता है। व्रत के दिन व्यक्ति को सांसारिक कार्यों से मन हटाकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए, ताकि उसकी चेतना ऊर्ध्वमुखी बनी रहे। यही कारण है कि इस दिन ऐसे कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है जो मन को बाहरी संसार में बांध दें।

वास्तव में सुई और धागा प्रतीक हैं "बंधन" और "कर्म" के। सुई जोड़ती है, धागा बांधता है, और सिलाई का अर्थ है दो वस्तुओं को एक सूत्र में पिरोना। जबकि व्रत का भाव है — मुक्ति, समर्पण और ईश्वर के प्रति एकनिष्ठता। जब स्त्री व्रत रखती है, तो वह अपने सांसारिक कर्मबंधनों से एक दिन के लिए विरक्ति लेकर भगवान से एकत्व का अनुभव करती है। इसीलिए उसे कहा गया — आज कुछ मत सिलना, क्योंकि यह दिन कुछ जोड़ने का नहीं, बल्कि सब छोड़कर ईश्वर में विलीन होने का है।

तांत्रिक और योगशास्त्र की दृष्टि से भी इसका गहरा अर्थ है। जब व्यक्ति उपवास करता है, तो उसके भीतर की प्राणशक्ति अत्यंत संवेदनशील हो जाती है। उसका शरीर सूक्ष्म ऊर्जा से परिपूर्ण रहता है। इस अवस्था में किसी नुकीली या धातु की वस्तु से कार्य करना ऊर्जा प्रवाह में व्यवधान डाल सकता है। सुई का स्पर्श नाड़ियों के ऊर्जावान संतुलन को क्षीण कर सकता है, जिससे मन अशांत हो जाता है। प्राचीन काल में जब स्त्रियां ऊर्जा-संतुलन और ध्यान में दक्ष थीं, तब यह अनुभवजन्य सत्य के रूप में जाना गया था। कुछ परंपराओं में तो यह भी कहा गया है कि व्रत के दिन सुई या कैंची का उपयोग करना अशुभ होता है, क्योंकि ये वस्तुएं "छेदन" या "विभाजन" का प्रतीक हैं। व्रत का दिन प्रेम, एकता और साधना का होता है, ऐसे में विभाजन या काटने-जोड़ने का प्रतीक कार्य ऊर्जा के स्तर पर नकारात्मक कंपन पैदा करता है। यही कारण है कि दादी-नानी अपने अनुभव से कहती थीं — आज सुई मत चलाना, वरना पूजा का पुण्य घट जाएगा।

कहते हैं एक बार एक गांव में सावित्री नाम की स्त्री करवाचौथ का व्रत कर रही थी। दिनभर उपवास रखने के बाद वह शाम को चांद निकलने का इंतजार कर रही थी। तभी उसके कपड़े का किनारा फट गया। उसने सोचा, "थोड़ी देर ही तो है, सिल लेती हूं।" जैसे ही उसने सुई उठाई, उसका हाथ हल्का-सा चुभ गया और खून निकल आया। उसी समय आंगन में रखा दीपक बुझ गया। सावित्री घबरा गई और तुरंत सुई रख दी। बुजुर्ग सास ने कहा, "बिटिया, व्रत का दिन साधना का होता है, इस दिन शरीर में जो ऊर्जा होती है वह बहुत पवित्र और कोमल होती है, उसमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।" सावित्री ने वह बात गांठ बांध ली और जीवनभर व्रत के दिन सुई को हाथ नहीं लगाया। आज विज्ञान के युग में भी यदि देखा जाए तो इस परंपरा के पीछे मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक संतुलन का गहरा तर्क है। जब व्यक्ति व्रत रखता है, तो शरीर और मन दोनों विश्राम की अवस्था में जाते हैं। ऐसे में सूक्ष्म और श्रमसाध्य कार्य शरीर को तनाव और असंतुलन में ला सकते हैं। इसलिए धर्म ने इसे परंपरा का रूप देकर साधना की एकाग्रता बनाए रखने का मार्ग बनाया। व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मसंयम और ध्यान का अभ्यास है। सुई-धागा न चलाने की यह परंपरा हमें यह याद दिलाती है कि इस दिन का उद्देश्य संसार को जोड़ना नहीं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। जब मन शांत, कर्म स्थिर और भक्ति अखंड होती है, तभी व्रत का सच्चा फल प्राप्त होता है। यही वह रहस्य है जिसे हमारी दादी-नानी सहज भाषा में कहती थीं — "व्रत के दिन सुई मत चलाना, बेटी, वरना पूजा का पुण्य घट जाएगा।"

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

मेहसाणा में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस-उत्तर गुजरात के दूसरे दिन क्षेत्रीय एमएसएमई कॉन्क्लेव आयोजित

यदि एमएसएमई समृद्ध होंगे तो गुजरात समृद्ध होगा और गुजरात समृद्ध होगा तो विकसित भारत का विजन भी साकार होगा
-श्री संदीप सागले (आईएएस), आयुक्त, एमएसएमई

कॉन्क्लेव के दौरान 'क्लस्टरों से प्रतिस्पर्धात्मकता तक : वैश्विक व्यापार के लिए एमएसएमई को सक्षम बनाना' विषय पर पैनल चर्चा आयोजित हुई

(जीएनएस)। गांधीनग : मेहसाणा में चल रही दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी)-उत्तर गुजरात के दूसरे दिन यानी शुक्रवार, 10 अक्टूबर को क्षेत्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) कॉन्क्लेव आयोजित हुई। इस कॉन्क्लेव की मुख्य थीम 'उद्यम उत्कर्षः मजबूत एमएसएमई, सशक्त भारत' थी।

गुजरात सरकार के एमएसएमई आयुक्त श्री संदीप सागले (आईएएस) ने क्षेत्रीय एमएसएमई कॉन्क्लेव की शुरुआत की। उन्होंने कॉन्क्लेव की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। श्री सागले ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दो दशक पहले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की संकल्पना की थी और वर्ष 2003 में इस समिट की शुरुआत के साथ यह संकल्पना साकार हुई थी। आज इस समिट के फायदों को गुजरात के क्षेत्रीय स्तरों तक पहुंचाने के लिए पूरे गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जो 'विकसित भारत@2047' के विजन को मूर्त रूप देगा।

गुजरात के एमएसएमई सेक्टर की चर्चा करते हुए श्री संदीप सागले ने कहा कि गुजरात के एमएसएमई कठोर परिश्रम और लचीलेपन का प्रतीक हैं। ये एमएसएमई लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, गुजरात के औद्योगिक आउटपुट और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान देते हैं और इसके जरिए भारत की जीडीपी में भी योगदान देते हैं।

उन्होंने कहा कि आज, जब हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब हमें इस बात पर फोकस करना होगा कि अनिश्चितता से भरी इस दुनिया में हमारे एमएसएमई न केवल अपना अस्तित्व बचाए रखें, बल्कि विकास करने के साथ-साथ समृद्ध भी हों। उन्होंने एमएसएमई को मजबूत करने के लिए कस्टमर फोकस (ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना), ग्लोबल इंटीग्रेशन (वैश्विक एकीकरण), डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन (डिजिटल बदलाव) और रेजिलिएन्स एवं इनोवेशन (लचीलापन एवं नवाचार) सहित कुल चार मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही।

उन्होंने अपनी चर्चा का समापन करते हुए कहा कि गुजरात ने हमेशा भारत के औद्योगिक विकास का नेतृत्व किया है, और वह भी केवल अपने कद के आधार पर नहीं, बल्कि पूरी स्पिरिट यानी उत्साह और भाव के साथ। हमारे एमएसएमई इसी स्पिरिट को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें अपने एमएसएमई को मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर एमएसएमई समृद्ध होंगे तो गुजरात समृद्ध होगा और गुजरात समृद्ध होगा तो विकसित भारत का विजन भी साकार होगा।

इसके बाद, वाधवाणी फाउंडेशन के संस्थापक श्री मितुल पटेल ने 'गुजरात के एमएसएमई की विकास क्षमताओं को उजागर करना' (अलॉकिंग द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ गुजरात्स एमएसएमईस) विषय पर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि वाधवाणी फाउंडेशन का विजन विकसित भारत के अनुरूप है। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में एमएसएमई के महत्व के साथ ही इस बारे में भी अपना विजन प्रस्तुत किया कि कैसे ये एमएसएमई गुजरात और भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करेंगे। इसके अलावा, उन्होंने उत्तर गुजरात के

वर्चुअल बिजनेस ग्रोथ एक्सेलरेटर के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए।

तत्पश्चात, 'क्लस्टरों से प्रतिस्पर्धात्मकता तक : वैश्विक व्यापार के लिए एमएसएमई को सक्षम बनाना' (फ्रॉम क्लस्टर्स टू कॉम्पिटिटिवनेस : इनेबलिंग एमएसएमईस फॉर ग्लोबल ट्रेड) विषय पर पैनल चर्चा का आयोजन हुआ। पैनल चर्चाओं में छोटे उद्योगों को निर्यात विविधीकरण, मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी ढंग से उपयोग, टैरिफ (टैक्स) व्यवस्थाओं की जानकारी और व्यापार अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए लचीलेपन के विकास के माध्यम से वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत होने के लिए मार्गदर्शन दिया गया।

पैनल चर्चा में भारत में रूस की जीआर और फाइनेंस सेक्टर तथा व्यापार प्रतिनिधित्व की प्रमुख सुश्री ज्लाटा अंतुशेवा, दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डीआईसीसीआई) के संस्थापक सह चेयरमैन डॉ. मिलंद कांबले, इंडिया एक्जिम फिनसर्व की प्रबंध निदेशक और सीईओ सुश्री हिरवा ममतोरा, मंत्र एग्री सोल्यूशन प्रा.लि. के सीईओ श्री जयदीप भाटिया, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान के महानिदेशक डॉ. आशुतोष मुरकुटे और Sberbank इंडिया के निदेशक श्री शंखो गुप्ता ने भाग लिया। पैनल चर्चा में मॉडरेटर की भूमिका विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के संयुक्त महानिदेशक डॉ. राहुल सिंह ने निभाई।

इस पैनल चर्चा में नियामक ढांचे को समझकर सप्लाई चैन की चुनौतियों को संबोधित करते हुए टैरिफ और नीतिगत बदलावों के सामने लचीलापन विकसित करते हुए और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता एवं स्थिरता मानदंडों के साथ संरेखित करते हुए एमएसएमई को उनके वैश्विक फुटप्रिंट का विस्तार करने के लिए ज्ञान और रणनीति से लैस करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस पैनल चर्चा ने एमएसएमई के लिए बाजार सुलभता, निर्यात विविधीकरण और वैश्विक संबंधों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान की, जो एमएसएमई को क्लस्टरों से आगे बढ़ने, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदान करने और 2047 के विकसित भारत के विजन में योगदान देने के लिए सक्षम बनाएगी।

कार्यक्रम के अंत में दक्षिण रेलवे के श्री विहार ठाकर, ओएनजीसी-मेहसाणा के श्री रवि जैन, मारुति सुजुकी-गुजरात प्लांट के श्री मंदार गाडगिल और टाटा अग्रतास के श्री आनंद सोडा द्वारा वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योग संबंधों को मजबूत बनाना और स्थानीय उद्योग विकास को बढ़ावा देना है।

उल्लेखनीय है कि दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी)-उत्तर गुजरात का आयोजन 'हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी' मंत्र के साथ मेहसाणा स्थित गणपत विश्वविद्यालय में 9 और 10 अक्टूबर, 2025 को किया गया है। यह पूरे गुजरात में आयोजित होने वाली चार वीजीआरसी की श्रृंखला की पहली कॉन्फ्रेंस है, जिसका उद्घाटन कल यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने किया था। यह रीजनल कॉन्फ्रेंस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की सफलता और विरासत के आधार पर आयोजित की गई है। यह कॉन्फ्रेंस राज्य की क्षेत्रीय क्षमताओं को प्रदर्शित करेगी, जमीनी स्तर के विकास का उपयोग करेगी और 'विकसित भारत@2047' और 'विकसित गुजरात@2047' के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप होगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'राष्ट्र प्रथम' भाव को उजागर करने वाली अनूठी प्रस्तुति 'मेरा देश पहले' गुजरात में सर्वप्रथम गिफ्ट सिटी में आयोजित हुई

मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों, सामाजिक जीवन के अग्रणियों, वरिष्ठ उद्योगकारों तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने इस मंचन को देखा

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आकार ले रहे नए भारत के रूपांतरण की एक अनूठी कहानी 'मेरा देश पहले' का गुजरात में सर्वप्रथम शो 10 अक्टूबर शुक्रवार को गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में आयोजित हुआ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों, सामाजिक जीवन के अग्रणियों, वरिष्ठ उद्योगकारों तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने इस मंचन को देखा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सदैव राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है। उनके समग्र जीवन की अनेक घटनाएँ-प्रसंग देशवासियों में देशप्रेम, समर्पण तथा 'राष्ट्र प्रथम' के भाव के लिए प्रेरणादायी बने हैं। 'मेरा देश पहले' श्री नरेन्द्र मोदी की उस अद्वितीय यात्रा को मेगा शो द्वारा जीवंत करता है।

'मेरा देश पहले' देश के अन्य राज्यों में सफल तथा प्रशंसनीय मंचन के बाद गुजरात में पहली बार गिफ्ट सिटी परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें निःशुल्क प्रवेश रखा गया था।

प्रसिद्ध सर्जक श्री मनोज मुंतशिर निर्मित 'मेरा देश पहले' का मंचन निहारने के लिए आमंत्रित सहित ऑनलाइन पंजीकरण से प्रवेश प्राप्त करने वाले नागरिक पहुँचे और उन्होंने इस प्रस्तुति को देखा।

पठानकोट-जम्मू तवी सेक्शन लैंड स्लाइडिंग के चलते अवरोध के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी

उत्तर रेलवे के कठुआ-माधोपुर पंजाब में डाउन लाइन पर ब्रिज संख्या 17 पर मिसअलाइमेंट होने एवं पठानकोट-जम्मू तवी सेक्शन में लैंड स्लाइडिंग के चलते अवरोध के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी।जिसका विवरण निम्नानुसार है:

पूर्णतः रद्द ट्रेनें

- 11 अक्टूबर 2025 की गाडी संख्या 19027, बांन्द्रा टर्मिनस-जम्मूतवी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- 13 अक्टूबर 2025 की गाडी संख्या 19028, जम्मूतवी-बांन्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- 12 अक्टूबर 2025 की गाडी संख्या 19415, साबरमती-श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- 14 अक्टूबर 2025 की गाडी संख्या 19416, श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा-साबरमती एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
- गाडी संख्या 19107, भावनगर टर्मिनस-एमसीटीएम उधमपुर एक्सप्रेस अगली सूचना तक रद्द रहेगी।
- गाडी संख्या 19108, एमसीटीएम उधमपुर-भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस अगली सूचना तक रद्द रहेगी।

आंशिक रद्द ट्रेने

- गाडी संख्या 19027, बांन्द्रा टर्मिनस-जम्मूतवी एक्सप्रेस 18 अक्टूबर 2025 से अगली सूचना तक लुधियाना स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा यह ट्रेन लुधियाना-जम्मूतवी के बीच आंशिक रद्द रहेगी।
- गाडी संख्या 19028, जम्मूतवी-बांन्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 20 अक्टूबर 2025 से अगली सूचना तक जम्मूतवी के स्थान पर लुधियाना से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा यह ट्रेन जम्मूतवी-लुधियाना के बीच आंशिक रद्द रहेगी।
- गाडी संख्या 19415, साबरमती-श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा 19 अक्टूबर 2025 से अगली सूचना तक अमृतसर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा यह ट्रेन अमृतसर-श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा के बीच आंशिक रद्द रहेगी।
- गाडी संख्या 19416, श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा-साबरमती एक्सप्रेस 21 अक्टूबर 2025 से अगली सूचना तक श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा के स्थान पर अमृतसर से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा यह ट्रेन श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा-अमृतसर के बीच आंशिक रद्द रहेगी।
- गाडी संख्या 19223, साबरमती-जम्मूतवी 15 अक्टूबर 2025 तक फिरोजपुर केंट स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा यह ट्रेन फिरोजपुर केंट-जम्मूतवी के बीच आंशिक रद्द रहेगी।
- गाडी संख्या 19224, जम्मूतवी-साबरमती एक्सप्रेस 15 अक्टूबर 2025 तक जम्मूतवी के स्थान पर फिरोजपुर केंट से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा यह ट्रेन जम्मूतवी-फिरोजपुर के बीच आंशिक रद्द रहेगी।

ट्रेन के ठहराव, संरचना एवं समय-सारणी संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया भारतीय रेल की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन करें।

पश्चिम रेलवे द्वारा त्योहारी सीज़न 2025 के दौरान व्यापक भीड़ प्रबंधन व्यवस्था

यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र सुरक्षित और व्यवस्थित त्योहारी यात्रा सुनिश्चित करने हेतु पश्चिम रेलवे की सक्रिय तैयारी

(जीएनएस)। त्योहारी सीज़न के दौरान यात्रियों के सुरक्षित और व्यवस्थित बोर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए समर्पित होल्डिंग एरिया आगामी त्योहारों के दौरान होने वाली भीड़ और यात्रियों की आवाजाही में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा सुरक्षित, सुचारू और कुशल रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधा उपाय शुरू किए गए हैं। मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस, बोरीवली, वापी, वलसाड, उधना और सूरत सहित प्रमुख स्टेशनों पर विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सभी निर्दिष्ट यात्री आवास क्षेत्रों में बैठने की व्यवस्था, पेयजल सुविधा, शौचालय, पर्याप्त रोशनी, पंखे और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली जैसी

आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। यात्रियों के प्रवेश और टिकटिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक स्थान पर अतिरिक्त काउंटर स्थापित किए गए हैं, साथ ही कतार नियमन, सहायता और सुरक्षा के लिए प्रत्येक स्टेशन पर लगभग 20 अतिरिक्त टिकट चेकिंग स्टाफ और आरपीएफ कर्मियों की तैनाती भी की गई है।

श्री विनीत ने आगे बताया कि ट्रेन प्रस्थान से पहले प्रतीक्षारत यात्रियों को आराम से समायोजित करने के लिए सभी प्रमुख स्टेशनों पर पर्याप्त कवर्ड होल्डिंग क्षमता बनाई गई है। बांद्रा टर्मिनस पर, प्लेटफ़ॉर्म संख्या 1 के पूर्व की ओर प्रवेश द्वार के पास 210 वर्ग मीटर से अधिक का आश्रय क्षेत्र उपलब्ध कराया गया है, जबकि वापी में, यात्रियों के एकत्र होने के लिए एफओबी लैंडिंग के पास 110 वर्ग मीटर से अधिक का कवर्ड क्षेत्र तैयार किया गया है। उधना स्टेशन को पूरे मंडल में सबसे बड़ी होल्डिंग क्षमता प्रदान की गई है, जिसमें स्टेशन के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर 3200 वर्ग मीटर से अधिक के तीन चिह्नित कवर्ड स्थान हैं, जिनमें से एक क्षेत्र वर्तमान में होल्डिंग क्षमता को और बढ़ाने के लिए निर्माणाधीन है। इसी प्रकार, सूरत में, 1,200 वर्ग मीटर से अधिक के दो निर्दिष्ट होल्डिंग क्षेत्र तैयार किए गए हैं, एक पीआरएस कार्यालय से सटे पश्चिमी प्रवेश द्वार के पास और दूसरा बुकिंग कार्यालय के पास पूर्व की ओर जिससे त्योहारों के समय होने वाली भीड़ के दौरान व्यवस्थित रूप से यात्रियों को लाने और नियमित रूप से चढ़ने में मदद मिलेगी।

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों से अपील की गई है कि वे प्लेटफॉर्म या प्रवेश द्वारों के पास भीड़ लगाने के बजाय निर्धारित प्रतीक्षालयों का उपयोग करें, ताकि व्यस्त समय के दौरान आवाजाही सुचारू रूप से नियंत्रित की जा सके। यात्रियों से ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों के दिशानिर्देशों का पालन करने का भी आग्रह किया गया है, क्योंकि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य सभी यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देना है। त्योहारों की भीड़ के दौरान कम समय में हजारों यात्रियों के ट्रेनों में चढ़ने की उम्मीद के साथ व्यवस्था बनाए रखने और समय पर प्रस्थान सुनिश्चित करने में सामूहिक सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कर्मचारी हित निधि (SBF) - भावनगर मंडल के द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम – 2025 का आयोजन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल पर कर्मचारी हित निधि (Staff Benefit Fund - SBF) के तत्वावधान में "महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम – 2025" के अंतर्गत "Financial Discipline and Wealth Habits for Women" विषय पर एक ऑफ़लाइन सेमिनार का सफल आयोजन किया गया।

यह सेमिनार दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 को सांय 16.00 बजे मंडल कार्यालय सभागृह, भावनगर परा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी एवं अध्यक्ष, कर्मचारी हित निधि समिति श्री हुबलाल जगन की अध्यक्षता में किया गया।

कार्यक्रम में Advisor Skill Development Organisation के प्रशिक्षक श्री देवदत्त आर. पाठक ने महिला रेलकर्मियों एवं अधिकारियों को "वित्तीय अनुशासन और धन संबंधी आदतें" विषय पर उपयोगी मार्गदर्शन

एवं प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने आर्थिक योजना, निवेश की समझ एवं वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम महिला कर्मचारियों में वित्तीय साक्षरता एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

इस अवसर पर सहायक कार्मिक अधिकारी श्री राधेश्याम जी के मार्गदर्शन में कल्याण शाखा की टीम द्वारा कार्यक्रम का सुंदर एवं सुव्यवस्थित आयोजन किया गया। महिला कर्मचारियों ने इस सेमिनार में सक्रिय भागीदारी करते हुए इसे अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक बताया।

प्रथम वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का समापन

दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में विभिन्न सेक्टर्स में 1212 एमओयू से भविष्य में उत्तर गुजरात में अनुमानित 3.24 लाख करोड़ रुपए का संभावित निवेश आने से क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई तथा उद्योग मंत्री श्री बलवंतसिंह राजपूत की प्रेरक उपस्थिति

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल -:

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को सरकार के साथ जोड़कर 'स्वच्छता से सेमीकंडक्टर' तक; हर क्षेत्र में विकास की ऊंचाइयां पार की हैं
- प्रधानमंत्री का लोगों की सहभागिता से हर गाँव-हर क्षेत्र में लोगों तक विकास पहुँचाने का विजन वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस से पूरा होगा
- प्रथम वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की सफलता का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री के सतत मार्गदर्शन, पार्टनर कंट्रीज के सहयोग, देश-विदेश के प्रतिनिधियों तथा टीम गुजरात के कर्मयोगियों को जाता है
- प्रथम रीजनल कॉन्फ्रेंस की सफलता 'वोकल फॉर लेकल' तथा 'गांव से ग्लोबल' की दिशा में अविरत आगे बढ़ना का विश्वास दृढ़ बनाती है

'चार्टिंग अ पाथ टुवर्ड्ज विकसित गुजरात@2047' पुस्तक का अनावरण

प्रतिष्ठित हथकरघा एवं हस्तकला अवॉर्ड तथा एमएसएमई वुमन अवॉर्ड प्रदान किए गए

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को सरकार के साथ जोड़कर 'स्वच्छता से सेमीकंडक्टर' तक के हर क्षेत्र में विकास की ऊंचाइयां पार की हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के विकास केवल नगरों या बड़े शहरों तक सीमित न रहने और हर गाँव-हर क्षेत्र के लोगों को उसका सहभागी बनाने तथा विकास उन तक भी पहुंचाने के विजन से वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का राज्य में आयोजन हुआ है।

श्री पटेल मेहसाणा जिले के खेरवा स्थित गणपत विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित उत्तर गुजरात की दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के शुक्रवार को हुए समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने 'वेल बिगन इज हाफ डन' उक्ति का उल्लेख करते हुए जोड़ा कि प्रधानमंत्री ने ग्लोबल विलेज तथा वोकल फॉर लोकल का जो विचार दिया, उसे प्रथम रीजनल कॉन्फ्रेंस की सफलता ने बल दिया है। मुख्यमंत्री ने उत्तर गुजरात की इस वीजीआरसी की फलश्रुति का वर्णन करते हुए कहा कि दो दिनों में 21 क्षेत्रों में निवेश के लिए 1212 एमओयू हुए। इनके द्वारा उत्तर गुजरात में आगामी समय में अनुमानित 3.24 लाख करोड़ रुपए का संभावित निवेश आएगा और इस क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

उन्होंने इस वीजीआरसी की ऐसी अप्रतिम सफलता का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सतत मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने पार्टनर कंट्रीज, कॉन्फ्रेंस में जुड़े देश-विदेश के प्रतिनिधियों, केन्द्र सरकार के मंत्रियों तथा टीम गुजरात के कर्मयोगियों को भी इस सफलता का हकदार बताया। श्री भूपेंद्र पटेल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के दिशादर्शन में अब तक 10 वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सफलतापूर्वक आयोजित की गईं और हर समिट में हमें नई ऊर्जा, रोजगार के नए अवसर तथा नए निवेश मिले हैं। अब क्षेत्रीय वाइब्रेंट कॉन्फ्रेंस का प्रयोग और विस्तृत एवं प्रासंगिक बना है। उत्तर गुजरात की इस प्रथम रीजनल कॉन्फ्रेंस की सफलता दर्शाती है कि राज्य में विकास 'गांव से ग्लोबल' की दिशा में अविरत आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2003 में वाइब्रेंट समिट के विचार को तत्कालीन समय में चुनौतियों के बीच साकार कर वाइब्रेंट समिट को उत्तरोत्तर उपलब्धियाँ दिलाए जाने का विस्तार से विश्लेषण किया।

उन्होंने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में आयोजित चर्चा सत्रों, प्रेजेंटेशन्स तथा एमओयू रीजनल डेवलपमेंट का नया अध्याय रचेंगे। उन्होंने आगामी समय में आयोजित होने वाली अन्य अंचलों की रीजनल कॉन्फ्रेंस में लोगों की सक्रियता की अपेक्षा व्यक्त की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2003 में वाइब्रेंट समिट

का आयोजन कर जो दीर्घदृष्टि दिखाई थी, वह अब फलीभूत हुई है। उनके इस मॉडल से प्रेरित होकर आज देश के अन्य राज्य भी ऐसे इवेंट का आयोजन कर रहे हैं। कोरोना काल की चुनौतियों के बावजूद वाइब्रेंट की यात्रा अविरत जारी रही है। अब, गुजरात के चार क्षेत्रों में से एक उत्तर गुजरात से रीजनल वाइब्रेंट की शुरुआत हुई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर गुजरात पूरे राज्य का श्रेष्ठ रीजन बनकर उभरेगा।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री बलवंतसिंह राजपूत ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को विकास में सहभागी बनाने के उम्दा उद्देश्य के साथ की गई है। इस पहले संस्करण में दो दिनों तक लघु, मध्यम और मेगा उद्योगों तथा हितधारकों के साथ गुणवत्ता और कौशल विकास जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और समझौता ज्ञापनों (एमओयू) किए गए हैं।

श्री राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के छोटे से छोटे व्यक्ति की चिंता करते हैं। युद्ध, टैरिफ (टैक्स) और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के समय में भी जीएसटी सुधारों और 12 लाख रुपए तक की आय पर आयकर छूट देने जैसे निर्णयों के माध्यम से वे 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए देश को प्रोत्साहित कर रहे हैं। गुजरात में भी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मजबूत नेतृत्व में सिंगल विंडो सिस्टम और उद्योग-उन्मुख नीतियों के परिणामस्वरूप राज्य में कारोबार सुगमता के श्रेष्ठ वातावरण का निर्माण हुआ है। उद्योग और खान विभाग की प्रधान सचिव सुश्री ममता वर्मा ने कहा कि रीजनल वाइब्रेंट समिट राज्य के समान और संतुलित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कॉन्फ्रेंस से क्षेत्रीय स्तर पर उद्योगों के बीच परस्पर भागीदारी, नेटवर्किंग और विचारों का आदान-प्रदान संभव हुआ है, जिससे उद्योग और रोजगार के नए क्षेत्रों को उभरने का अवसर मिलेगा। उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप ने दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस की सफलता का वर्णन करते हुए कहा कि इस समिट में 34 विदेशी कंपनियों ने हिस्सा लिया है। 170 से अधिक स्टार्टअप्स भी शामिल हुए हैं। छोटे-बड़े सभी उद्योगपति इसमें सहभागी बने हैं। 80 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ यह समिट वैश्विक बन गई है। कृषि सेमिनार में जापान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और नीदरलैंड जैसे देशों ने हिस्सा लिया। देश और दुनिया से कुल 29,000 रजिस्ट्रेशन हुए, जिनमें 440 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए। महेन्द्रा एग्री के सीईओ श्री अशोक शर्मा और वेलस्पन समूह की सहायक कंपनी वेलस्पन न्यू एनर्जी लिमिटेड के सीईओ श्री कपिल माहेश्वरी ने रीजनल वाइब्रेंट कॉन्फ्रेंस के आयोजन की सराहना करते हुए गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के इकोसिस्टम की प्रशंसा की। उन्होंने, विशेषकर आलू खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में गुजरात की प्रगति को लेकर अपने सकारात्मक विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी, अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती अंजू शर्मा, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस.जे. हैदर, गणपत विश्वविद्यालय के संस्थापक श्री गणपत पटेल, महिन्द्रा के सीईओ श्री देवेन्द्र सिंह सहित उद्योग जगत के कई अग्रणी, शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि और औद्योगिक एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

यूपी में टूटा सपा-कांग्रेस गठबंधन, कांग्रेस अकेले लड़ेगी एमएलसी चुनाव, अजय राय ने घोषित किए 5 उम्मीदवार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच बना गठबंधन अब औपचारिक रूप से टूट गया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को आगामी विधान परिषद (एमएलसी) शिक्षक और स्नातक निर्वाचन 2025 के लिए अपने पांच प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सभी 11 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।

अजय राय ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस युवाओं और शिक्षकों की आवाज को विधान परिषद में बुलंद करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पांच लाख स्नातक और दो लाख शिक्षक मतदाताओं के फार्म भरवाकर वोटर बनवाने का अभियान तेज कर दिया है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक कनेक्ट सेंटर बनाया गया है, जो हर जिले से सीधे जुड़ा रहेगा। प्रत्येक जिले में कोऑर्डिनेटर कमेटी का गठन किया जा रहा है और सभी फ्रंटल

संगठनों, विधि, शिक्षक और चिकित्सा प्रकोष्ठों को इस अभियान में विशेष जिम्मेदारी दी गई है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हर सीट पर चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों को फिलहाल कोऑर्डिनेटर प्रत्याशी घोषित किया जा रहा है। अब तक पार्टी ने पांच सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं —

- मेरठ-सहारनपुर स्नातक सीटः विक्रांत वशिष्ठ
- आगरा स्नातक सीटः रघुराज सिंह पाल
- लखनऊ स्नातक सीटः डॉ. देवमणि तिवारी
- वाराणसी शिक्षक सीटः संजय प्रियदर्शी
- वाराणसी स्नातक सीटः अरविंद सिंह पटेल

अजय राय ने बताया कि सभी सीटों पर सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे और अन्य वरिष्ठ नेता चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए जिलों में बैठकें करेंगे।

उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार में शिक्षक, बेरोजगार युवा, कर्मचारी, डॉक्टर, वकील – सभी वर्ग परेशान हैं। सरकारी पदों पर भर्तियां रुकी हुई हैं, विज्ञापन निकलने के बावजूद परीक्षाएं नहीं हो रहीं और जो परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं।

अजय राय ने कहा कि भाजपा सरकार में शिक्षक वर्ग सबसे अधिक पीड़ित है। वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय नहीं दिया जा रहा, एडेड कॉलेजों के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा समाप्त कर दी गई और पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन तो कर दिया, लेकिन आयोग एक भी भर्ती कराने में असफल रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "2021 में निकले विज्ञापनों की परीक्षाएं आज तक नहीं हो पाईं। पांच बार तिथि बदलने के बाद भी परीक्षा टाल दी गई। अब समय आ गया है कि शिक्षक और स्नातक वर्ग इस कुशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे।"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने बूथ कैप्चरिंग और मतपेटी बदलवाने जैसे तरीकों से लोकतंत्र की हत्या की थी। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस इस बार पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी और "लोकतंत्र की असली आवाज़" को सदन में पहुंचाने का काम करेगी।

इस घोषणा के साथ ही यह तय हो गया है कि यूपी के एमएलसी चुनाव में कांग्रेस और सपा अब अलग-अलग मैदान में उतरेंगी, जिससे राज्य की राजनीतिक जंग और दिलचस्प होने जा रही है।

हाईस्कूल शिक्षक भर्ती पर फिर संकट के बादल, सरकारी सिस्टम में उलझी नियुक्ति प्रक्रिया

रांचीः झारखंड में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया एक बार फिर सरकारी उलझनों की भेंट चढ़ गई है। साल 2016 में निकली इस भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों की उम्मीदें एक बार फिर अधर में लटक गई हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने हाल ही में हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ एलपीए (लॉन्ग पब्लिक अपील) दायर करने का निर्णय लिया है, जिससे बहुप्रतीक्षित नियुक्ति प्रक्रिया फिर से अटक गई है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 1 सितंबर को आदेश दिया था कि विज्ञापन में घोषित 2034 रिक्त पद योग्य रिट पिटिशनर के माध्यम से भरे जाएं और पूरी प्रक्रिया छह महीने में पूरी की जाए। कोर्ट ने आठ सप्ताह के भीतर JSSC सचिव से रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया था। इस आदेश से अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी थी कि वर्षों से लंबित भर्ती अब पूरी होगी, लेकिन आयोग के एलपीए दायर करने के फैसले ने उस उम्मीद को फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

सरकार के इस निर्णय से अभ्यर्थियों में गहरा आक्रोश और निराशा है। हालांकि राहत की बात यह है कि न्यायालय ने अभी तक इस अपील को स्वीकार नहीं किया है और न ही कोई अंतरिम आदेश पारित किया गया है। इसी कारण 1 सितंबर के

आदेश के अनुसार कुछ अभ्यर्थी अब भी JSSC कार्यालय में जाकर अपनी दावेदारी दे रहे हैं।

कोडरमा के पवन कुमार मंडल, जो नौ साल से नौकरी की प्रतीक्षा में हैं, ने बताया कि उन्होंने कटऑफ पार किया था, फिर भी चयन सूची में नाम नहीं आया। पलामू के मार्केंडेय मिश्रा और देवघर की दिव्या ने भी यही अनुभव साझा किया कि योग्य होते हुए भी उन्हें भर्ती से बाहर रखा गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार और आयोग लगातार नई तकनीकी आपत्तियाँ लगाकर प्रक्रिया को टालते जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि हजारों पद अब भी रिक्त हैं।

झारखंड हाईकोर्ट ने इस भर्ती के लिए सरकार को "वन मैन कमीशन" बनाने का सुझाव दिया था ताकि पूरे विवाद की जांच कर योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। लेकिन सरकार ने उस दिशा में कदम बढ़ाने की बजाय डबल बेंच में अपील करने का निर्णय लिया, जिससे पूरी प्रक्रिया एक बार फिर कानूनी उलझनों में फंस गई है।

नौ वर्षों से सरकारी नौकरी की आस में भटक रहे शिक्षण अभ्यर्थी अब यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर शिक्षा विभाग और आयोग की असमंजसपूर्ण नीतियों का खामियाज़ा उन्हें कब तक भुगतना पड़ेगा। वहीं, राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि सरकार इस भर्ती को लेकर जल्द कोई ठोस फैसला नहीं लेती तो यह मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस-उत्तर

वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई की अध्यक्षता में उत्तर गुजरात के आर्थिक क्षेत्र के लिए तैयार किए गए आर्थिक मास्टर प्लान पर सेमिनार आयोजित

उत्तर गुजरात में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, नए निवेशक आएंगे और लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा : वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई

(जीएनएस)। गांधीनगर, : उत्तर गुजरात के मेहसाणा के खेरवा गांव में स्थित गणपत विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के दूसरे दिन, शुक्रवार को राज्य के वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई की अध्यक्षता में उत्तर गुजरात के आर्थिक क्षेत्र के लिए तैयार किए गए आर्थिक मास्टर प्लान पर सेमिनार और पैनल चर्चा का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने कहा कि यह मास्टर प्लान गुजरात के 33 जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार को मौजूदा 280 बिलियन डॉलर (वित्तीय वर्ष 2023) से बढ़ाकर 3.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक तक पहुंचाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने का रोडमैप है।

उन्होंने आगे कहा कि इस मास्टर प्लान के अंतर्गत उत्तर गुजरात में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, नए निवेशक आएंगे और लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित बनाने के स्वप्न को साकारक करने में यह मास्टर प्लान काफी उपयोगी सिद्ध होगा।

गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (ग्रिट) की एजीक्यूटिव कमेटी की चेयरमैन सह सीईओ श्रीमती एस. अपर्णा ने कहा कि गुजरात के ऐतिहासिक और आर्थिक दृष्टिकोण से छह महत्वपूर्ण एवं मुख्य आर्थिक क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इन क्षेत्रों में उत्तर गुजरात, कच्छ, मध्य गुजरात, सौराष्ट्र, तटीय सौराष्ट्र और सूरत शामिल हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने वीजीआरसी के पहले दिन यानी गुरुवार को राज्य के छह मुख्य आर्थिक क्षेत्रों के लिए तैयार किए गए क्षेत्रीय आर्थिक मास्टर प्लान (रीजनल इकोनॉमिक मास्टर प्लान) का अनावरण किया था।

उत्तर गुजरात के आर्थिक विकास के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, अरवल्ली और गांधीनगर को कवर करते हुए तैयार किए गए इस मास्टर प्लान में 23 से 24 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित पूंजी निवेश किया जाएगा। इस निवेश के अंतर्गत सवा पांच लाख करोड़ रुपए का निवेश राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा, जबकि अन्य पूंजी निवेश निजी कंपनियां, संस्थानों और इंडस्ट्रीज से लाया जाएगा। इस प्लान के माध्यम से उत्तर गुजरात में 12 मिलियन नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

इस प्रकार, इस प्लान के जरिए उत्तर गुजरात की आर्थिक प्रगति को एक नई गति मिलेगी। इसके अलावा, पूंजी निवेश के अनेक अवसर प्राप्त होंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इस अवसर पर नीति आयोग की प्रमुख आर्थिक सलाहकार श्रीमती अन्ना रॉय ने उत्तर गुजरात के आर्थिक विकास को लेकर तैयार किए गए मास्टर प्लान की सराहना की और राज्य सरकार एवं ग्रिट के कार्यों की प्रशंसा कर उन्हें बधाई भी दी।

इस अवसर पर सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव (योजना) श्रीमती आर्द्रा अग्रवाल और ग्रिट की श्रीमती श्रुति चरण और उद्योगपतियों सहित कई निवेशक मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि आर्थिक वृद्धि का लाभ युवाओं को मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में उद्योगों के सहयोग से रीजनल स्किलिंग सेंटर्स और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (ग्रीन स्किल्स, ब्लू इकोनॉमी, लॉजिस्टिक्स और एआई एकेडमी आदि) स्थापित किए जाएंगे। इन योजनाओं और आर्थिक गतिविधियों से राज्य के युवाओं के लिए लगभग 280 लाख नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस प्रकार, ये क्षेत्रीय मास्टर प्लान हरेक क्षेत्र की स्थानीय उत्पादन क्षमताओं के अनुरूप फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को लक्ष्य बनाएंगे।

सेबी ने बदला दंड ढांचा, अब ब्रोकर्स को मिलेगी राहत और पारदर्शिता बढ़ेगी

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने शेयर बाजार के ब्रोकर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of Doing Business) और अनुपालन को और सरल बनाने के उद्देश्य से सेबी ने शुक्रवार को अपने दंड प्रणाली में बड़ा सुधार किया। नए नियमों के तहत स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा ब्रोकर्स पर लगाए जाने वाले दंडों की संख्या 235 से घटाकर अब केवल 90 कर दी गई है।

सेबी की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में बताया गया कि पहले चरण में कुल 235 दंड प्रावधानों की गहन समीक्षा की गई। इनमें से 40 दंड पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं, जबकि 105 मामूली प्रक्रियागत उल्लंघनों को 'वित्तीय असुविधा' (Financial Disincentive) की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब छोटी तकनीकी गलतियों या औपचारिक प्रक्रियागत चूकों पर भारी जुर्माना लगाने के बजाय केवल मामूली

आर्थिक चेतावनी या असुविधा लागू होगी।

सेबी ने स्पष्ट किया कि नए दंड ढांचे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अलग-अलग एक्सचेंजों पर एक ही गलती के लिए कई बार जुर्माना न लगे। अब से केवल लीड एक्सचेंज को ही समान उल्लंघनों पर कार्रवाई का अधिकार होगा। इससे उन ब्रोकर्स को राहत मिलेगी जो कई एक्सचेंजों में सदस्यता रखते हैं और पहले एक ही गलती के लिए कई जगहों पर दंड भरते थे।

इसके अलावा, सेबी ने यह भी कहा कि अब कुछ उल्लंघनों के लिए सलाह या चेतावनी पर्याप्त मानी जाएगी, विशेषकर तब जब गलती पहली बार हुई हो। कई मामलों में दंड की राशि घटाई गई है और अधिकतम सीमा तय की गई है, ताकि ब्रोकर्स की प्रतिष्ठा को अनावश्यक क्षति न पहुंचे। यह नया संशोधित ढांचा न केवल भविष्य की कार्यवाहियों पर बल्कि पहले से चल रही जांचों पर भी लागू होगा, जिससे ब्रोकिंग समुदाय को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

सेबी ने यह भी माना कि "पेनाल्टी" शब्द अक्सर नकारात्मक छवि से जुड़ जाता है, जिससे छोटे उल्लंघनों पर भी ब्रोकर्स की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। इस कारण, सेबी ने प्रक्रियागत चूकों के लिए "पेनाल्टी" शब्द को हटाकर "फाइनेंशियल डिसइन्सेंटिव" का प्रयोग करने का निर्णय लिया है।

जानकारी के अनुसार, इस दिशा में सेबी ने एक्सचेंजों और ब्रोकर्स के प्रतिनिधियों की एक वर्किंग ग्रुप गठित की थी। इस समूह ने लंबे विचार-विमर्श और उद्योग जगत की प्रतिक्रिया के आधार पर यह नया ढांचा तैयार किया। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से भारतीय ब्रोकिंग इंडस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ेगी, अनावश्यक दंड का बोझ घटेगा और बाजार में भरोसा और अनुपालन की भावना को नया बल मिलेगा।

गुजरात के नागरिकों की परिवहन सेवा में हुई वृद्धि

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नागरिकों की सेवा में 201 नई एसटी बसों को हरी झंडी दिखाकर गांधीनगर से रवाना किया

परिवहन राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी की प्रेरक उपस्थिति

- नई बसों में 136 सुपर एक्सप्रेस, 60 सेमी लग्जरी और 5 मीडी बसें शामिल
- दिवाली के त्योहार में सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 4200 अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू
- एसटी निगम प्रतिदिन 8000 से अधिक बसों के संचालन के जरिए 27 लाख से अधिक यात्रियों को यातायात सेवाएं प्रदान करता है

गांधीनगर, 10 अक्टूबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के प्रत्येक नागरिक को उच्च गुणवत्ता युक्त, समयबद्ध और सुरक्षित परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग का नई टेक्नोलॉजी के साथ बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और बसों का आधुनिकीकरण करने के लिए लगातार मार्गदर्शन किया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और परिवहन राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी ने नागरिकों के लिए बस सेवाओं को और अधिक सुविधा युक्त बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को गांधीनगर से गुजरात राज्य परिवहन निगम (एसटी निगम) की 201 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न रूटों के लिए रवाना किया। इन बसों में 136 सुपर एक्सप्रेस, 60 सेमी लग्जरी और 5 मिडी बसें शामिल हैं। गांधीनगर में आयोजित बसों के लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री

और परिवहन राज्य मंत्री ने बसों का औपचारिक रूप से लोकार्पण कर बसों के ड्राइवर और कंडक्टरों को बधाई दी और उनका अभिवादन स्वीकार किया।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने दिवाली के अवसर पर 4200 अतिरिक्त बसों के संचालन का भी शुभारंभ किया ताकि राज्य का प्रत्येक नागरिक अपने परिवार के साथ त्योहार मना सके।

हाल ही में गुजरात एसटी निगम की ओर से भाद्रपद पूर्णिमा के दौरान अंबाजी के मेले के लिए 28,000 से अधिक, पावागढ़ शारदीय नवरात्रि के लिए 22,000 से अधिक और जन्माष्टमी के त्योहारों के दौरान 7000 से अधिक फेरों का संचालन कर नागरिकों को उत्तम परिवहन सेवा का परिचय दिया था।

उल्लेखनीय है कि गुजरात एसटी निगम प्रतिदिन 8000 से अधिक बसों के माध्यम से 33 लाख किलोमीटर का संचालन कर राज्य के 27 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाता है।

लोकार्पण समारोह में गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिल्पीबेन पटेल, गांधीनगर उत्तर की विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल, गांधीनगर दक्षिण के विधायक श्री अल्पेशभाई ठाकोर और माणसा के विधायक श्री जयंतीभाई पटेल के अलावा परिवहन विभाग और एसटी निगम के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

अहमदाबाद स्टेशन पुनर्विकास के अंतर्गत 100 वर्ष पुराने सारंगपुर रोड ओवर ब्रिज का पुनर्निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर

(जीएनएस)। सारंगपुर रोड ओवर ब्रिज पुनर्निर्माण से यातायात होगा और अधिक सुगम पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है पुनर्विकास कार्य के अंतर्गत सारंगपुर रोड ओवर ब्रिज (ROB) का पुनर्निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। यह पुल अहमदाबाद (कालूपुर) स्टेशन के दक्षिण दिशा में स्थित है और अंबेडकर चौक के पश्चिम दिशा में तथा रखियाल रोड को पूर्व दिशा में जोड़ता है। लगभग 100 वर्ष पुराने इस पुल के पुनर्निर्माण का कार्य जनवरी 2025 में रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) को सौंपा गया था। पुनर्निर्माण के बाद रेलवे हिस्से में लेन की संख्या बढ़ाकर छह कर दी जाएगी, जिससे वाहनों की आवाजाही में सुगमता आएगी और यातायात जाम में उल्लेखनीय कमी होगी। यह पुल अहमदाबाद स्टेशन के आगामी एलिवेटेड रोड नेटवर्क

से भी जुड़ेगा, जिससे यात्रियों और आम नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी।

पुल की कुल लंबाई दो हिस्सों में विभाजित है — एप्रोच की लंबाई 497 मीटर और रेलवे स्पैन की लंबाई 138 मीटर है, जिसमें 107 मीटर का सिंगल स्पैन बो-स्ट्रिंग गर्डर ब्रिज शामिल है। पुराने एप्रोच और रेलवे स्पैन को हटाने का कार्य पूरा हो चुका है। यह कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण था, जिसे रेलवे संचालन को प्रभावित किए बिना ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान सफलतापूर्वक पूरा किया गया। वर्तमान में कार्य तेजी से प्रगति पर है — 132 पाइलिंग कार्य पूरे हो चुके हैं, 23 में से 18 पिलर तैयार हैं तथा 76 में से 44 गर्डर ढाले जा चुके हैं। पूरे प्रोजेक्ट का कार्य अगस्त 2026 तक पूरा होने की संभावना है। इस पुल के निर्माण से अहमदाबाद स्टेशन क्षेत्र में यातायात व्यवस्था अधिक आधुनिक, सुरक्षित और सुगम बनेगी। यात्रियों, स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों को निर्बाध और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। RLDA इस महत्वपूर्ण परियोजना को निर्धारित 18 माह की अवधि में पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, जिससे अहमदाबाद शहर में बेहतर शहरी कनेक्टिविटी और सुगम आवागमन सुनिश्चित हो सकेगा।

सावलकोट परियोजना को केंद्र की मंजूरी, पाकिस्तान को घेरने की तैयारी

(जीएनएस)। श्रीनगर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर लगा दिया। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए चिनाब नदी के पानी पर रोक लगा दी। ऐसे में अब एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान पर जल प्रहार की तैयारी कर ली। सिंधु जल संधि के निलंबन के बीच केंद्र ने चिनाब नदी पर सावलकोट परियोजना को मंजूरी दी है। जिससे साफ होता है कि भारत का पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश है कि पानी को लेकर पुरानी रियायतों का दौरा खत्म हो चुका है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर 1,856 मेगावाट की सावलकोट जलविद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश की है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजना पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के निलंबन के बाद फिर से जीवित की जा रही है। लगभग चार दशकों से रुकी हुई, सावलकोट परियोजना चिनाब बेसिन में भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है और 1960 की संधि के तहत पश्चिमी नदी जल के अपने हिस्से का पूर्ण उपयोग करने के सरकार के प्रयासों का एक अहम हिस्सा है।

स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत पश्चिम रेलवे द्वारा स्वच्छ परिवेश और खाद्य स्वच्छता पर विशेष ध्यान

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, कारखानों और ट्रेनों में स्वच्छता, सफाई और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 1 से 15 अक्टूबर, 2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा 2025 मना रही है। इस अभियान के शुभारंभ और प्रारंभिक गतिविधियों के आधार पर 8वें और 9वें दिन स्वच्छ परिसर और स्वच्छ आहार पर केंद्रित पहलों के साथ अभियान आगे बढ़ा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आठवें दिन 8 अक्टूबर, 2025 को रेलवे कार्यालयों, कॉलोनियों, विश्राम/प्रतीक्षा कक्षों, विश्राम गृहों और शयनगृहों में स्वच्छता में सुधार हेतु सघन स्वच्छता/फ्यूमिगेशन अभियान चलाए गए। यात्रियों और रेलवे कॉलोनियों के निवासियों के लिए सूखे और गीले कचरे को अलग-

अलग करने के बारे में 70 से अधिक जागरूकता अभियान आयोजित किए गए। रेलवे कॉलोनियों में कचरा सफाई के लिए जनभागीदारी अभियान चलाया गया जिसमें 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 50 स्टेशनों/कॉलोनियों में वृक्षारोपण और भूनिर्माण गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

नौवें दिन, स्वच्छ आहार पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें खाद्य स्वच्छता, विक्रेता स्वच्छता और उचित अपशिष्ट निपटान प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रेलवे परिसरों में गहन निरीक्षण किए गए। अधिकारियों और मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा स्वच्छता और स्वच्छ खाद्य हैंडलिंग प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगभग 100 फूड स्टॉल, फूड कार्ट, क्लाउड किचन और भंडारण क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। खानपान कर्मचारियों के बीच स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 200 से अधिक कैंटीन धारकों, रसोइयों और खाद्य विक्रेताओं की चिकित्सा और स्वच्छता जांच की गई। गतिविधि के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता और सुरक्षित खाद्य हैंडलिंग प्रथाओं पर जागरूकता भी बढ़ाई गई। बर्तन सफाई प्रक्रियाओं, कचरा निपटान प्रणाली, समग्र स्वच्छता और कर्मचारियों की चिकित्सा फिटनेस का आकलन करने के लिए रनिंग रूम, रेस्ट हाउस और कैंटीन सहित औचक निरीक्षण किए गए।

पश्चिम रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पहल के अंतर्गत स्टेशनों, कॉलोनियों और खानपान इकाइयों में व्यापक स्वच्छता, सफाई और जागरूकता अभियान चलाए गए। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता में सुधार, सुरक्षित भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देना और सक्रिय जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना था।

केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने गुजरात के पहले ग्रीन रेलवे स्टेशन – एकतानगर का किया दौरा

(जीएनएस)। केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने दिनांक 09 अक्टूबर 2025 को भारत के सबसे सुंदर और आधुनिक रेलवे स्टेशनों में से एक तथा गुजरात के पहले "ग्रीन रेलवे स्टेशन" एकता नगर का दौरा किया।

श्री सोमन्ना ने रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण कर स्वच्छता, आधुनिक सुविधाओं एवं ग्रीन टेक्नोलॉजी से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

मीडिया को संबोधित करते हुए श्री सोमन्ना ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में भारतीय रेल ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार करते हुए उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2025- 26 में गुजरात को 17,155 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है, जो वर्ष 2009 -14 के आवंटन के मुकाबले 29 गुना है। वर्ष 2014 से अभी तक गुजरात में 2739 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया

तथा 3,144 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को विद्युतीकृत किया गया है। गुजरात राज्य में 87 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशनों के रूप में विकसित किया जा रहा है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हुए गुजरात में विभिन्न स्टेशनों पर 97 लिफ्टों और 50 एस्कलेटरों का निर्माण किया गया है, साथ ही 335 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस समय गुजरात राज्य में चार वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन हो रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एकता नगर, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट जैसे शहरों में रेलवे सुविधाओं को आधुनिक स्तर तक पहुँचाया गया है। प्रधानमंत्री के "विकसित भारत 2047" के विज़न में रेलवे की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

एकतानगर स्टेशन पर निरीक्षण से पहले माननीय रेल राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना जी ने आज वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के साथ सूरत-एकता नगर खंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने रेल पटरियों की सुरक्षा और परिचालन दक्षता की समीक्षा की। साथ ही उन्हें ट्रैक सेफ्टी एवं परिचालन दक्षता के साथ चल रही विकास परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई ।